झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 1241/2016

और इसके अनुरूप मामले

आपराधिक विविध याचिका संख्या 1241/2022

1. असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड, इसके निदेशक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं
   दीना असित मेहता उर्फ़ दीनाएमेहता
2. दीना असित मेहता उर्फ़ दीनाएमेहता
3. किरीट हिमतलाल वोरा, कृति एच. वोरा
4. मंगलम सिक्योरिटीज
   (सब ब्रोकर और याचिकाकर्ता संख्या 1 के बिजनेस एसोसिएट) अपने प्रोपराइटर हरिशंकर मोदी के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं।
5. हरिशंकर मोदी.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. राजेंद्र प्रसाद.....विरोधी पक्ष

के साथ

आपराधिक विविध याचिका संख्या 669/2008

1. (ख) मैसर्स असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड, प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. श्री असित सी. मेहता
3. श्रीमती दीना ए. मेहता .....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. राजेंद्र प्रसाद (एडवोकेट)
   उर्फ़ राजेन्द्र प्रसाद बसईवाला .....विरोधी पक्ष

के साथ

आपराधिक विविध याचिका संख्या 889/2008

हरिशंकर मोदी.....प्रार्थी

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. राजेंद्र प्रसाद (एडवोकेट)
   उर्फ़ राजेन्द्र प्रसाद बसईवाला .....विरोधी पक्ष

कोरम : माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री जितेंद्र एस सिंह, एडवोकेट।
	:	मोर अंकल नाथ तिवारी, एडवोकेट। [2016 के सीआरएमपी संख्या 1241 और 2008 के 669 में]
	:	कोई नहीं [2008 के सीआरएमपी संख्या 889 में]
राज्य के लिए	:	सुश्री नेहाला शर्मिन, विशेष पीपी

: श्री नवीन कुमार सिंह, ए.पी.पी.
: श्री जितेन्द्र पाण्डेय, ए.पी.पी.
ओपी संख्या 2 के लिए : श्री आर.एस.
: श्री ऋषव कुमार, एडवोकेट।

21/22.02.2024 श्री जितेंद्र एस. सिंह के साथ श्री ओंकार नाथ तिवारी, 2016 के सीआरएमपी संख्या 1241 और 2008 के सीआरएमपी संख्या 669, सुश्री नेहाला शर्मिन, श्री नवीन कुमार सिंह और श्री जितेंद्र पांडे, संबंधित मामलों में राज्य के लिए A.P.Ps और श्री आरएस मजूमदार, विद्वान वरिष्ठ के साथ सुनवाई की।

श्री ऋषव कुमार के साथ वकील, ओपी संख्या 2 के लिए उपस्थित विद्वान वकील।

2. 2008 के सीआरएमपी संख्या 889 में याचिकाकर्ता की ओर से किसी ने जवाब नहीं दिया है, इसीलिए याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में इस याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जा रही है।

<u>आपराधिक विविध याचिका संख्या 1241/2016</u>

3. इस याचिका में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायलय में लंबित पीसीआर वाद संख्या 192/2010 (टीआर संख्या 387/2016) की समस्त आपराधिक कार्यवाही तथा याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 तथा याचिका कर्ता संख्या 4 और 5 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत लिए गए अपराध का संज्ञान को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई

4. ओपी संख्या 2 द्वारा शिकायत का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त संख्या 1 एक स्टॉक ब्रोकर है और एक डिपॉजिटरी प्रतिभागी भी है और अभियुक्त संख्या 4 स्टॉक सब ब्रोकर और अभियुक्त संख्या 1 का सहयोगी है और दोनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ-साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयरों के स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में लगे हुए हैं और वे ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम दुमका के माध्यम से स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला स्कूल रोड, दुमका में अभियुक्त सं 4 के कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटर टमनलों के माध्यम

से उन ग्राहकों को जो स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके साथ पंजीकृत हैं,\

यह आगे कहा गया है कि अभियुक्त संख्या 2 प्रबंध निदेशक है और अभियुक्त संख्या 3 अभियुक्त संख्या 1 का पूर्णकालिक निदेशक है और वे कंपनी के व्यवसाय के संचालन और दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं और अभियुक्त संख्या 5 मालिक और प्रभारी व्यक्ति है और अभियुक्त संख्या 4 के व्यवसाय के संचालन और दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार है।

आगे यह भी कहा जाता है कि शिकायतकर्ता को उक्त स्टॉक ब्रोकिंग सेवा प्रदान करने के लिए, अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता के साथ दुमका में

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर, जिसके लिए उन्होंने दुमका में पावर ऑफ अटॉर्नी सहित एक पुस्तिका में निहित कई मुद्रित कागजात पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए, जिसे अभियुक्त संख्या 5 ने शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया और तदनुसार शिकायत अभियुक्त संख्या 4 के ग्रुप कोड और क्लाइंट आईडी के तहत एक ग्राहक के रूप में पंजीकृत की गई थी। कोड संख्या 116525 और 116526 थे नकद खंड और व्युत्पन्न खंड के लिए शिकायतकर्ता को आवंटित किया गया है।

मूल रूप में उक्त त्रिपक्षीय करार या तो स्टॉक ब्रोकर अभियुक्त संख्या 1 या स्टॉक सब ब्रोकर अभियुक्त संख्या 4 के साथ पड़ा है। अभियुक्त संख्या 5 ने शिकायतकर्ता को उक्त त्रिपक्षीय समझौते की नमूना प्रति प्रदान की है, जो उसके द्वारा विधिवत प्रमाणित है।

यह आगे कहा गया है कि उक्त त्रिपक्षीय समझौते के सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने शेयरों की खरीद के आदेश दिए और उक्त आदेश दुमका में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रेषण दुमका में किया गया था और तदनुसार शिकायतकर्ता के कोड संख्या 116525

के लिए अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा विभिन्न कंपनी के शेयर खरीदे गए थे और खरीदे गए शेयर शिकायतकर्ता के डीमैट खाते संख्या 1201320000495114 में रखे गए थे।

आगे यह कहा गया है कि 22.01.2008 को, अभियुक्त व्यक्तियों ने धोखाधड़ी और बेईमानी से त्रिपक्षीय समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया और असामान्य व्यवहार किया और शिकायतकर्ता को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके खिलाफ अभियुक्त को अन्य नोटिसों के अलावा, शिकायतकर्ता ने अपने कार्यालय नोटिस दिनांक 28.01.2008 के माध्यम से अभियुक्त संख्या 1 और 4 को खाता कोड संख्या 1 में कोई और लेनदेन (खरीदने या बेचने का) नहीं करने की सख्त चेतावनी दी 116525 शिकायतकर्ता के लिखित अनुरोध के बिना शिकायतकर्ता के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। उक्त नोटिस आरोपियों को पहले ही मिल चुका था।

आगे यह भी कहा गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों की भारी धोखाधड़ी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए, शिकायतकर्ता ने अपने नोटिस 19.09.2009 के तहत अभियुक्त को पहले दी गई तारीख के अनुसार शक्ति को रद्द कर दिया

दिनांक 19-09-2009 को फैक्स के माध्यम से अभियुक्त सं 1 को अभियुक्त सं 1 को भेजा गया था जो दिनांक 19-09-2009 को अपराह्न लगभग 109 बजे फैक्स के माध्यम से अभियुक्त सं 1 के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। दिनांक 19.09.2009 के उक्त नोटिस की प्रति भी कूरियर के माध्यम से अभियुक्त संख्या 4 और 5 को भेजी गई थी और इसे 22.09.2009 को अभियुक्त संख्या 4 को दिया गया था।

आगे यह भी कहा गया है कि अभियुक्त संख्या 1 ने इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर, नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के समक्ष एक मध्यस्थता आवेदन दायर किया, जिसने अपनी बारी पर बिना दिमाग

लगाए यांत्रिक रूप से मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू कर दी, जिसका असर मध्यस्थता मामला संख्या एफओ/के-0146/2008 हैऔर अवैध रूप से मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

आगे यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने मध्यस्थ की शक्ति और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति स्पष्ट रूप से अवैध, अमान्य, विकृत और कानून के प्रावधान के विपरीत थी, लेकिन मध्यस्थ ने अवैध रूप से 1,56,017-64 पैसे का अवार्ड दिया और 17.06.2009 को इस पर हस्ताक्षर किए और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 18.06.2009 के माध्यम से पुरस्कार को भेज दिया। शिकायतकर्ता इस दावे के साथ कि यदि कोई भी पक्ष पुरस्कार से संतुष्ट नहीं है, तो पीड़ित पक्ष पंचाट की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन के साथ उपयुक्त अदालत से संपर्क कर सकता है।

आगे यह कहा गया है कि एक तरफ अभियुक्त व्यक्तियों ने दुमका में शिकायतकर्ता को सूचित किया है कि वे मध्यस्थता मामले ए एम संख्या एफओ/के-0146/2008के अनुसरण में 1,56,017.64 रुपये की सम्मानित राशि की वसूली के लिए, शिकायतकर्ता के स्टॉक को 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, 2009 को 1,56,967.19 रुपये की राशि बेच दी है, लेकिन दूसरी ओर अभियुक्त संख्या 1 और 4 ने संयुक्त रूप से विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश दुमका की अदालत के समक्ष 05.11.2009 को शपथ पत्र के साथ विधिवत समर्थित अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया। स्वत्व मध्यस्थता सूट संख्या 44/2009 में, जिसमें, उन्होंने सम्मानित राशि के गैर-वसूली के बारे में स्वीकार किया है\

<u>विविध याचिका संख्या 669/2008</u>

1. इस याचिका में 11.03.2008 के संज्ञान लेने के आदेश सहित पूरी आपराधिक

कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 120-बी के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है, जो न्यायिक दण्ड अधिकारी प्रथम श्रेणी दुमका के न्यायलय में लंबित पीसीआर वाद संख्या 83/2008 (टीआर संख्या 854/2008) के सम्बन्ध में है

2. ओपी संख्या 2 द्वारा शिकायत का मामला दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त संख्या 1 एसईबीआई के साथ स्टॉक एक्सचेंज का पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर है और अभियुक्त संख्या 2 और 3 क्रमशः अभियुक्त संख्या 1 के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और वे अभियुक्त संख्या 1 के आचरण और दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं।

अभियुक्त संख्या 4 सेबी के साथ पंजीकृत सब-ब्रोकर है और अभियुक्त संख्या 1 का सहयोगी और फ्रेंचाइजी है और अभियुक्त संख्या 5 मालिक और प्रभारी है और अभियुक्त संख्या 4 के आचरण और दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक मामलों के लिए जिम्मेदार है।

शिकायतकर्ता की वास्तविकता और वित्तीय सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त संख्या 5 ने अभियुक्त संख्या 2 और 3 के साथ मिलीभगत और मिली भगत से शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि अभियुक्त संख्या 1 स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी प्रतिभागी का पंजीकृत सदस्य है।

अभियुक्त व्यक्तियों ने दुमका में शिकायतकर्ता के साथ स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयरों के लेन-देन के लिए शिकायतकर्ता को स्टॉकब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया और तदनुसार शिकायतकर्ता को दुमका में अभियुक्त संख्या 4 के साथ पंजीकृत किया गया। इसके बाद, ग्राहक आईडी कोड संख्या 116525 शिकायतकर्ता को नकद खंड के लिए आवंटित किया गया था और ग्राहक आईडी कोड संख्या 116526 भविष्य के खंड के लिए आवंटित किया गया था और शिकायतकर्ता के पक्ष में एक डीमैट खाता खोला गया था।

अपने ब्रोकिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को भविष्य खंड में पैसे निवेश करने के लिए प्रेरित किया

। अभियुक्त संख्या 5 ने शिकायतकर्ता को नकदी खंड के कुछ शेयरों को अभियुक्त संख्या 1 को सुरक्षा के रूप में सौंपने के लिए प्रेरित किया और शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि सुरक्षा, यदि शिकायतकर्ता द्वारा जमा की जाती है तो उसे एक अलग खाते में रखा जाएगा और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा और अभियुक्त व्यक्तियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए, शिकायतकर्ता ने अभियुक्त संख्या 1 को नकदी खंड के निम्नलिखित शेयर सौंपे:

रिलायंस कम्युनिकेशन - 100 पीस

रिलायंस कैपिटल - 50 पीस

इंफोसिस - 30 पीस

दिनांक 14.12.2007 की अनुदेश पर्ची के आधार पर, उपर्युक्त शेयरों को शिकायतकर्ता के डीमैट खाते से 22.12.2007 को अभियुक्त संख्या 1 के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।

दिनांक 22-01-2008 को अभियुक्त व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर, जानबूझकर, बेईमानी से और धोखे से शिकायतकर्ता की संहिता में पडे भावी खंडों को बेच दिया जो अभियुक्त व्यक्तियों की अभिरक्षा और नियंत्रण में थे।

दिनांक 25-01-2008 को शिकायतकर्ता ने नोटिस के माध्यम से अभियुक्त व्यक्तियों के कपटपूर्ण कृत्य का विरोध किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने दिनांक 28.01.2008 के नोटिस के तहत अभियुक्त व्यक्तियों से सुरक्षा शेयरों को यथावत रखने का अनुरोध किया लेकिन अभियुक्त व्यक्तियों ने 13.02.2008 को सुरक्षा के पूरे हिस्से बेच दिए और पूरी राशि का दुर्विनियोजन कर दिया।

अभियुक्त संख्या 2 और 3 के साथ आपराधिक साजिश में अभियुक्त

संख्या 5 ने शिकायतकर्ता को धोखा दिया और धोखाधड़ी और बेईमानी से शिकायतकर्ता को अभियुक्त संख्या 1 को सुरक्षा के रूप में नकद खंड के शेयर देने के लिए प्रेरित किया और शिकायतकर्ता ने इस तरह के प्रलोभन पर काम किया।

<u>विविध याचिका संख्या 889/2008</u>

1. इस याचिका में 11.03.2008 के संज्ञान लेने के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 120-बी के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है।

जिसके सम्बन्ध में पीसीआर वाद संख्या 83/2000 (टी आर संख्या 854/2008)

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुमका के न्यायालय में लंबित है।

1. वर्तमान मामले के तथ्य आपराधिक विविध याचिका संख्या 669/2008के मामले के तथ्यों के समान हैं, क्योंकि वर्तमान मामले में भी इसी शिकायत को चुनौती दी गई है।

2. आपराधिक विविध याचिका संख्या 1241/2016 में याचिकाकर्ताओं के लिए पेश होने वाले वकील श्री जितेंद्र एस सिंह ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है, जो शेयरों और स्टॉक में काम करती है। वह प्रस्तुत करता है कि उक्त कंपनी एक सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी प्रतिभागी है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 2 याचिकाकर्ता कंपनी का प्रबंध निदेशक है और याचिकाकर्ता संख्या 3 उक्त कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक है। वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता संख्या 4 सेबी के साथ पंजीकृत एक सब ब्रोकर है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता संख्या 4, जो दुमका शहर में स्थित *मैसर्स मंगलम सिक्योरिटीज* के नाम और शैली के तहत अपना व्यवसाय चलाता है। श्री सिंह प्रस्तुत करते हैं कि आपराधिक

विविध याचिका संख्या 669/2008 में, याचिकाकर्ता संख्या 1 शेयर और प्रतिभूतियों में एक व्यापारी कंपनी है और याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 याचिकाकर्ता कंपनी के प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक हैं। वह प्रस्तुत करता है कि ओपी संख्या 2 के पास याचिकाकर्ता कंपनी के साथ डीमैट खाता है जिसमें ग्राहक कोड संख्या 116525 है जो नकद खंड में सौदा करता है और व्युत्पन्न खंड में भी सौदा करता है। वह प्रस्तुत करता है कि ओपी संख्या 2 एक समझौते में प्रवेश करके स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों और शेयरों में व्यापार करने के लिए याचिकाकर्ता कंपनी का ग्राहक बन गया। श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि आरोप शेयर लेनदेन के संबंध में लगाए गए हैं और इसके लिए याचिकाकर्ता कंपनी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (संशोधित) के तहत विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता खंड को लागू किया है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता का मामला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) की देखरेख में आयोजित किया गया था और 18.06.2009 का अधिनिर्णय याचिकाकर्ता-कंपनी के पक्ष में था और ओपी संख्या 2 को पुरस्कार (अवार्ड) की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर 1,56,017.64 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। वह प्रस्तुत करता है कि विवाद पहले से ही मध्यस्थता में तय किया गया है कि मामला एक नागरिक विवाद से उत्पन्न हो रहा है, जो आपराधिक मामले का विषय नहीं हो सकता है। श्री सिंह विस्तार से बताते हैं

उनका तर्क और प्रस्तुत करता है कि 15.09.2009 को, याचिकाकर्ता कंपनी ने 14.09.2009 को ओपी संख्या 2 को एक पत्र भेजा जिसमें सूचित किया गया था कि

उपरोक्त पुरस्कार (अवार्ड) को ओ.पी संख्या 2 पूरा करे वह आगे प्रस्तुत करता है कि ओपी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता कंपनी को दिनांक 19.09.2009 को एक पत्र जारी किया जिसके तहत उसने पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर दिया है। वह प्रस्तुत करता है कि उक्त शक्ति निरसन के बाद समझौते के मद्देनजर 15 दिनों के लिए मौजूद थी। वह प्रस्तुत करता है कि ओपी संख्या 2 के निर्देश पर, याचिकाकर्ता

कंपनी ने समझौते में सहमति के अनुसार 03.10.2009 से तत्काल प्रभाव से लेनदेन बंद कर दिया। उनके अनुसार याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा कथित अवार्ड राशि की वसूली से पहले, याचिकाकर्ताओं को ओपी संख्या 2 द्वारा 2009 के मध्यस्थता सूट संख्या 44 को दाखिल करने या विद्वान अदालत द्वारा कोई स्थगन या कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद ओपी संख्या 2 ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409 की कथित धारा पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुमका के समक्ष पीसीआर केस संख्या 192/2010 दायर किया।

10.श्री सिंह, समझौते के खंड-1.7.5 का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता खंड है और परिसमापन भी वहां प्रदान किया गया है। खंड -2.1 का उल्लेख करने के माध्यम से, वह प्रस्तुत करता है कि क्षति या असर के प्रभाव का वर्णन किया गया है और वह आगे खंड -2.1 के उप-खंड-ए को संदर्भित करता है और प्रस्तुत करता है कि वायदा व्यापार में सभी स्थितियों का दैनिक निपटान शामिल है। वह खंड-2.1 के उप-खंड-बी को संदर्भित करता है और प्रस्तुत करता है कि यदि

ओपी संख्या 2 समय सीमा तक अतिरिक्त मार्जिन जमा करने में विफल रहा या यदि खाते में कोई बकाया ऋण होता है, तो दलाल/सदस्य पूरी स्थिति या स्थानापन्न प्रतिभूतियों के एक हिस्से को समाप्त कर सकता है और

ओपी संख्या 2 ऐसे शेयर बाजार में गिरावट के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने आगे कहा कि ओपी संख्या 2 ने दुमका में जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष एक उपभोक्ता मामला दायर किया है, जिसे 28.06.2016 को खारिज कर दिया गया था। वह 18.06.2009 के मध्यस्थता पुरस्कार का उल्लेख करता है और प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता की कंपनी के पक्ष में 1,56,017.64 रुपये की राशि दी गई थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है, जो अभी भी लंबित है। इन आधारों पर वह प्रस्तुत करता है कि एक नागरिक गलत के लिए, दुर्भावनापूर्ण रूप से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ओपी संख्या 2 द्वारा आपराधिक मुकदमा शुरू किया

गया है।

11.याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने ***विजय कुमार घई और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य***, (2022) 7 एससीसी 124 **में रिपोर्ट किया** गया, जिसमें पैरा -27 से 41.3 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है: -

> ***"27.*** *भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 "आपराधिक विश्वासघात" को परिभाषित करती है जो निम्नानुसार है:*
>
> *"**405.** आपराधिक विश्वास भंग,**जो** कोई, किसी रीति से संपत्ति को सौंपा जा रहा है, या संपत्ति पर किसी प्रभुत्व के साथ, बेईमानी से दुर्विनियोजन करता है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करता है, या उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या व्ययन करता है, कानून के किसी भी निर्देश के उल्लंघन में उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, जिसमें उस तरीके को निर्धारित किया गया है, या किसी कानूनी अनुबंध का, व्यक्त या निहित, जिसे उसने इस तरह के ट्रस्ट के निर्वहन को छूने के लिए बनाया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित करता है, " आपराधिक विश्वास भंग " करता है।*
>
> *आपराधिक विश्वास भंग के अपराध के आवश्यक तत्व हैं:*
>
> *a. अभियुक्त को संपत्ति या उस पर प्रभुत्व के साथ सौंपा जाना चाहिए,*
>
> *b. इस प्रकार सौंपे गए व्यक्ति को उस संपत्ति का उपयोग करना चाहिए, या;*
>
> *c. अभियुक्त को बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या निपटान करना चाहिए या जानबूझकर उल्लंघन में ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ित करना चाहिए,*
>
> *i. कानून के किसी भी निर्देश में उस* तरीके *को निर्धारित करना जिसमें इस तरह के ट्रस्ट का निर्वहन किया जाना है, या;*

ii. इस तरह के ट्रस्ट के निर्वहन को छूने वाले किसी भी कानूनी अनुबंध का।

28. *दंड संहिता, 1860 की धारा 405 के तहत संपत्ति का "सुपुर्द" इसके तहत अपराध का गठन करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रयुक्त शब्द हैं, किसी भी तरीके से संपत्ति को सौंपा गया। इसलिए, यह सभी प्रकार के सौंपे जाने तक फैला हुआ है, चाहे क्लर्क, नौकर, व्यापार भागीदार या अन्य व्यक्तियों को, बशर्ते वे "विश्वास" की स्थिति धारण कर रहे हों। एक व्यक्ति जो लगाए गए दायित्व की शर्तों के विपरीत उन्हें सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है, वह आपराधिक विश्वास भंग के लिए उत्तरदायी है और धारा 1*

दंड संहिता की धारा 406 के तहत दण्डित किया जाता है

29. *धारा में परिभाषा संपत्ति को केवल चल या अचल तक सीमित नहीं करती है। यह न्यायालय आर.के. डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन [आर.के. डालमिया बनाम दिल्ली प्रशासन, (1963) 1 एससीआर 253: एआईआर 1962 एससी 1821* में अवधारित किया कि चल संपत्ति की अपेक्षा संघिता में शब्द “संपत्ति” का प्रयोग व्यापक सन्दर्भ में है

और "संपत्ति" शब्द के अर्थ को केवल चल संपत्ति तक सीमित करने का कोई अच्छा कारण नहीं है जब इसका उपयोग धारा 405 में किसी भी योग्यता के बिना किया जाता है।

30. सुधीर शांतिलाल मेहता बनाम *सीबीआई [सुधीर शांतिलाल मेहता* बनाम *सीबीआई, (2009) 8 एससीसी 1 :*

(2009) 3 एससीसी (सीआरआई) 646] में यह देखा गया था कि आपराधिक विश्वास भंग के कार्य का अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ उस व्यक्ति द्वारा संपत्ति का उपयोग या निपटान करना होगा जिसे सौंपा गया है या अन्यथा उस पर प्रभुत्व है। ऐसा कार्य न केवल बेईमानी से किया जाना चाहिए, बल्कि कानून के किसी भी निर्देश या ट्रस्ट को पूरा करने से संबंधित किसी भी अनुबंध के उल्लंघन में भी

किया जाना चाहिए।

31. भारतीय दण्ड संहिता की धारा *415 "धोखाधड़ी" को परिभाषित करती है जो निम्नानुसार है:*

*"**415.** धोखाधड़ी--जो कोई, किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखे से या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी संपत्ति का परिदान करने के लिए प्रलोभित करता है या यह सहमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपने पास रखेगा, या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रलोभित करेगा या ऐसा कुछ करने का लोप करेगा जो वह नहीं करेगा या यदि वह इस प्रकार धोखा नहीं देता तो उसका लोप कर देता है, और कौन सा कार्य या चूक शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में उस व्यक्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है या होने की संभावना है, इसे "धोखा" कहा जाता है।*

धोखाधड़ी के अपराध के आवश्यक तत्व हैं:

a. किसी भी व्यक्ति का धोखा

b. (क) धोखे से नहीं तो बेईमानी से उस व्यक्ति को प्रलोभन देना-

i. किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को वितरित करने के लिए; नहीं तो

ii. सहमति देने के लिए कि कोई भी व्यक्ति बनाए रखेगा

कोई भी संपत्ति; नहीं तो

(ख) जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करने या छोड़ने के लिए प्रेरित करना जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि उसे इतना धोखा नहीं दिया गया था, और जो कार्य या चूक शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में उस व्यक्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाने का कारण बनती है या होने की संभावना है।

32. एक धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन अपराध का एक अनिवार्य घटक है। एक व्यक्ति जो बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को वितरित करने के लिए प्रेरित करता है, धोखाधड़ी के अपराध के लिए उत्तरदायी है।

33. भारतीय दण्ड संहिता की धारा *415 "धोखाधड़ी*

और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी को प्रेरित करने" को परिभाषित करती है जो निम्नानुसार है:

*"**420. धोखा देना और बेईमानी से संपत्ति का परिदान** करने को प्रेरित **करना**- जो कोई धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से धोखेबाज व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपति देने के लिए, या किसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए, या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है, और जो मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है, बनाने के लिए प्रेरित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।*

34. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 *धोखाधड़ी का एक गंभीर रूप है जिसमें संपत्ति के वितरण के साथ-साथ मूल्यवान प्रतिभूतियों के संदर्भ में प्रलोभन (किसी को नेतृत्व करने या स्थानांतरित करने के लिए) शामिल है। यह धारा उन मामलों पर भी लागू होती है जहां संपत्ति का विनाश धोखाधड़ी या प्रलोभन के कारण होता है। धोखाधड़ी के लिए सजा इस धारा के तहत प्रदान की जाती है जो 7 साल तक बढ़ सकती है और व्यक्ति को जुर्माना भी देती है।*

35. संपत्ति के वितरण को प्रेरित करने में धोखाधड़ी के अपराध को स्थापित करने के लिए, निम्नलिखित अवयवों को साबित करने की आवश्यकता है:

(१)व्यक्ति द्वारा किया गया अभ्यावेदन झूठा था।

(२) अभियुक्त *को पहले से पता था कि उसने जो निरूपण किया है वह झूठा है।*

अभियुक्त द्वारा उस व्यक्ति को धोखा देने के लिए बेईमान इरादे से प्रतिनिधित्व करना जिसे यह बनाया गया था।

(३) वह कार्य जहां अभियुक्त ने व्यक्ति को संपति देने या प्रदर्शन करने या किसी भी कार्य से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जो व्यक्ति ने नहीं किया होता *या अन्यथा* करता \

36. जैसा कि आरके विजयसारथी बनाम सुधा सीताराम [आरके विजयसारथी बनाम सुधा सीताराम, (2019) 16 एससीसी 739: (2020) 2 एससीसी (सीआरआई) में इस न्यायालय द्वारा देखा और आयोजित किया गया था।

454] के अनुसार, धारा 420 के अधीन अपराध का गठन करने के लिए सामग्री इस प्रकार है:

(१) एक व्यक्ति को धारा 415 के तहत धोखाधड़ी का अपराध करना चाहिए; और

(२) धोखा देने वाले व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित किया जाना चाहिए:

(अ) किसी भी व्यक्ति को संपत्ति वितरित करना; नहीं तो

(आ) मूल्यवान सुरक्षा या हस्ताक्षरित या सील की गई और मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम कुछ भी बनाना, बदलना या नष्ट करना। इस प्रकार, धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध का गठन करने के लिए धोखाधड़ी एक आवश्यक घटक है।

***7.** उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य [उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य, (2005) 10 एससीसी 336: (2006) 2 एससीसी में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी (सीआरआई) 49] लगभग समान तथ्यों और परिस्थितियों के साथ इस स्तर पर ध्यान देने के लिए प्रासंगिक हो सकता है: (एससीसी पीपी 338-39, पैरा 6-7)*

"6. अब हमारे द्वारा जांच की जाने वाली प्रश्न यह है कि क्या शिकायत की याचिका में बताए गए तथ्यों पर धारा 420/120-बीआईपीसी के तहत कोई भी आपराधिक अपराध बहुत कम अपराध है। अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत याचिका में एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया था कि जब उन्हें 4,20,000 रुपये का बीमा दावा प्राप्त होता है, तो वे उसमें से शिकायतकर्ता को 2,60,000 रुपये का भुगतान करेंगे, लेकिन इसका भुगतान कभी नहीं किया गया। ... शिकायतकर्ता की ओर से बताया गया कि अभियुक्त ने धोखे से

शिकायतकर्ता सहमत हो ताकि अभियुक्त व्यक्ति 4,20,000 रुपये के दावे के संबंध में उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए कदम उठा सकें। यह सुस्थापित है कि संविदा का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन्हीं मामलों में संविदा का उल्लंघन धोखाधड़ी माना जाएगा जहां प्रारंभ से ही कोई धोखा खेला गया हो। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो इसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में, यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि शुरुआत में ही अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का इरादा था जो धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।

7. हमारे विचार में, शिकायत की याचिका किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है, धारा 420 या धारा 120-बीआईपीसी के तहत किसी भी अपराध को तो बिल्कुल भी कम करती है और वर्तमान मामला पार्टियों के बीच विशुद्ध रूप से नागरिक विवाद का मामला है, जिसके लिए उपाय एक उचित रूप से गठित मुकदमा दायर करके सिविल कोर्ट के समक्ष निहित है। हमारी राय में, इन तथ्यों के मद्देनजर पुलिस जांच को जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करके इसे रद्द करना उचित और समीचीन था, जिसे उसने गलती से अस्वीकार कर दिया है।

38. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि केवल अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में एक आपराधिक अपराध नहीं है और नुकसान की नागरिक देयता को जन्म देता है। हालांकि, जैसा कि इस न्यायालय ने हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य [हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य (2000) 4 एससीसी 168/2000 एससीसी (सीआरआई) 786] के मामले में कहा था। के अनुसार, केवल संविदा भंग करने और धोखाधड़ी, जो कि आपराधिक अपराध है, के बीच का अंतर एक जुर्माना है। जबकि अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने को जन्म नहीं दे सकता है, धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा

धोखाधड़ी के अपराध का आधार है। मामले में, उत्तरदाता 2 द्वारा दायर शिकायत अपीलकर्ताओं के बेईमान या धोखाधड़ी के इरादे का खुलासा नहीं करती है

38. *वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड* बनाम *केरल राज्य [वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम केरल राज्य, (2015) 8 एससीसी 293: (2015) 3 एससीसी*बनाम

(सीआरआई) 498], इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एससीसी पीपी 297-98, पैरा 13)

"13. यह सच है कि तथ्यों का एक दिया गया सेट एक नागरिक गलत के साथ-साथ एक आपराधिक अपराध भी बना सकता है और केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के लिए एक नागरिक उपचार उपलब्ध हो सकता है जो स्वयं एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। असली परीक्षा यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं। वर्तमान मामले में, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि शुरुआत में ही अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का कोई इरादा था जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। हमारे विचार में, शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है। आपराधिक कार्यवाही को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब यह दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया जाता है। इस शक्ति का प्रयोग करते समय उच्चतर न्यायालयों को न्याय के सिरों की सेवा करने का भी प्रयास करना चाहिए। हमारी राय में, इन तथ्यों के मद्देनजर पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उच्च न्यायालय ने [मणिप्रसाद बनाम केरल राज्य, 2011 एससीसी ऑनलाइन केर 4251] कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करने में त्रुटि की है।

39. *शिकायत/*प्राथमिकी *और यहां तक कि चार्जशीट का अध्ययन करने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि* प्राथमिकी *में दिए गए कथन और अपीलकर्ता के*

खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोप भारतीय दण्ड संहिता *की धारा 405 और 420* भारतीय दण्ड संहिता, *1860 के तहत अपराध हैं। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां अभियुक्त की ओर से अपना वादा निभाने में विफलता के संबंध में आरोप लगाए जाते हैं, वादा करने के समय दोषी इरादे के अभाव में अनुपस्थित होने पर, धारा 420* भारतीय दण्ड संहिता *के तहत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है। तत्काल मामले में, यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि*

38. *वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड* बनाम *केरल राज्य [वेसा होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम केरल राज्य, (2015) 8 एससीसी 293: (2015) 3 एससीसी*बनाम

(सीआरआई) 498], इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एससीसी पीपी 297-98, पैरा 13)

"13. यह सच है कि तथ्यों का एक दिया गया सेट एक नागरिक गलत के साथ-साथ एक आपराधिक अपराध भी बना सकता है और केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के लिए एक नागरिक उपचार उपलब्ध हो सकता है जो स्वयं एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। असली परीक्षा यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं। वर्तमान मामले में, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि शुरुआत में ही अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का कोई इरादा था जो धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। हमारे विचार में, शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है। आपराधिक कार्यवाही को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब यह दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया जाता है। इस शक्ति का प्रयोग करते समय उच्चतर न्यायालयों को न्याय के सिरों की सेवा करने का भी प्रयास करना चाहिए। हमारी राय में, इन तथ्यों के मद्देनजर पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उच्च न्यायालय ने [मणिप्रसाद

बनाम केरल राज्य, 2011 एससीसी ऑनलाइन केर 4251] कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करने में त्रुटि की है।

39. शिकायत/एफआईआर और यहां तक कि चार्जशीट का अध्ययन करने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि एफआईआर में दिए गए कथन और अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोप आईपीसी की धारा 405 और 420 आईपीसी, 1860 के तहत अपराध हैं। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां अभियुक्त की ओर से अपना वादा निभाने में विफलता के संबंध में आरोप लगाए जाते हैं, वादा करने के समय दोषी इरादे के अभाव में अनुपस्थित होने पर, धारा 420 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है। तत्काल मामले में, यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि

अपीलकर्ताओं का प्रतिवादी के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था जो पार्टियों के बीच 20-8-2009 के समझौता ज्ञापन से स्पष्ट रूप से कटौती योग्य है।

40. विवाद का पूरा मूल उत्तरदाता *2 द्वारा किए गए निवेश से उत्पन्न होता है, जिसके बदले में 2.5 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 25-3-2008 में 2,50,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे, अंत में समझौता ज्ञापन दिनांक 20-8-2009 में समाप्त हुआ। इस समझौता ज्ञापन के आधार पर उत्तरदाता 2 ने तीन शिकायतें दर्ज कीं, दो दिल्ली में और एक कोलकाता में। इस प्रकार, उत्तरदाता 2 द्वारा कार्रवाई के एक ही कारण यानी एमओयू दिनांक 20-8-2009 से उत्पन्न दो एक साथ कार्यवाही शुरू की गई थी, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जो वर्जित है। शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है*

a. 6-6-2012 को, उत्तरदाता 2 ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीजेएम, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली के साथ धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की; जिसे 19-9-2016 को वापस ले लिया गया था।

b. कंपनी अधिनियम की धारा 68 के साथ पठित

धारा 200 सीआरपीसी के तहत सीएमएम, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली के समक्ष दायर शिकायत; जो लंबित है।

C. 28-3-2013 को, पीएस बउबाजार, सेंट्रल डिवीजन, कोलकाता को एक शिकायत की गई थी, जिसे अंततः पुलिस की धारा 406, 420, 120-बी दंड संहिता, 1860 के तहत एफआईआर संख्या 168 के रूप में दर्ज किया गया था।

12. उपरोक्त *निर्णय के आधार पर वह प्रस्तुत कर्त्ये है कि उपरोक्त* मामले के तथ्य और वर्तमान मामले के तथ्य समान हैं, इसके अनुसार पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

13. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ***ने एसके गोयल और अन्य*** बनाम झारखंड राज्य और अन्य**, (**2023) 3 जेसीआर 569 (जेएचआर) में रिपोर्ट किया गया। ***के मामले में भरोसा किया।*** उक्त निर्णय के पैरा -14 और 15 को यहां उद्धृत किया गया है: -

> *"14. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करता है कि पूरा मामला एक नागरिक (सिविल) विवाद से उत्पन्न हुआ है और सिविल विवाद के लिए, एफआईआर दर्ज करने के माध्यम से आपराधिकता डाल दी गई है और यदि नागरिक (सिविल) विवाद है, तो आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी*
>
> *जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है,* ***GHCL कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट बनाम इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड,*** *में रिपोर्ट किया गया* ***(2003) 4 एससीसी 505****. पैरा -12 और 13 को नीचे उद्धृत किया गया है: - "12. शिकायत परिवादऔर उसमें लगाए गए आरोपों के अवलोकन से हमें कुछ नहीं मिलता किसी भी अनुच्छेदों में कि उस शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी 2 से 7 के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए हैं। शिकायत के पैरा 2 में, यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी 2 से 6 कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों की देखभाल कर रहे हैं। शिकायतकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि ने किसके साथ बातचीत की, यह भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है। हालांकि शिकायत के पैरा 11 में यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता ने कई मौकों पर अभियुक्त 2 से 7 से मुलाकात की और राशि वापस करने का अनुरोध किया, लेकिन फिर से <u>शिकायतकर्ता</u>*

ने बैठक की तारीख के बारे में विशिष्ट आरोप नहीं लगाया है और यह व्यक्तिगत बैठक थी या सामूहिक बैठक। इसी प्रकार, शिकायत के पैरा 17 में यह आरोप नहीं है कि किसी विशेष निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक ने जाली नोट बनाया। पूरी शिकायत में उत्तरदाताओं 2 से 7 के खिलाफ गलत और अस्पष्ट आरोप हैं.

कानूनी प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि विश्वास भंग या धोखाधड़ी का मामला एक नागरिक गलत और आपराधिक अपराध दोनों है, लेकिन कुछ स्थितियों के तहत जहां कथित कार्य मुख्य रूप से एक नागरिक गलत होगा, ऐसा कार्य आपराधिक अपराध नहीं बनता है।

*15. वह प्रस्तुत करता है कि समान तथ्यों और परिस्थितियों में **एंजेल ब्रोकिंग लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य, (2018) एससीसी ऑनलाइन गुजरात 3772**, यह पाया गया कि आपराधिक नहीं है और भारतीय दंड संहिता की दंड धारा यानी 406 और 420 लागू नहीं हुई थी। उक्त निर्णय के पैरा- 2.1, 14 और 15 को नीचे उद्धृत किया गया है: -*

"2.1 शिकायतकर्ता संख्या 2 ने जामनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के साथ निजी शिकायत दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि, प्रतिवादी संख्या 2 का आवेदक कंपनी के साथ शेयर ट्रेडिंग और डीमैट खाता था

यह आरोप लगाया गया है कि बाजार में मंदी के कारण, प्रतिवादी संख्या 2 की पूर्व अनुमति के बिना, शिकायतकर्ता कंपनी ने शिकायतकर्ता के शेयरों को बहुत कम कीमत पर बेच दिया, जिससे शिकायतकर्ता को नुकसान हुआ और इस तरह के नुकसान की वसूली के लिए, आवेदक कंपनी ने 2,96,000/- रुपये की वसूली के लिए झूठे बिल जारी किए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता ने 08.05.2006 से 22.05.2006 तक लेनदेन का उल्लेख किया है, जिसमें शिकायतकर्ता के अनुसार, शेयर उच्च कीमत पर खरीदे गए थे और बहुत कम कीमत पर निपटाए गए थे, वह भी शिकायतकर्ता के खाते से और

शिकायतकर्ता की पीठ के पीछे।

14. रिकॉर्ड पर प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच करने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आवेदक कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का हस्तांतरण उसके व्यापार के उचित पाठ्यक्रम और पार्टियों के बीच समझौते के अनुरूप है। इसलिए, बाद में दर्ज आपराधिक मामला प्रतिवादी संख्या 2 की देयता को दूर करने के उद्देश्य से एक विचार प्रतीत होता है, जो लेनदेन से उत्पन्न हुआ है। यह भी पाया गया है कि हालांकि समझौते के खंड के तहत, विवाद को हल करने का उपाय किया जाता है, जिसमें सेबी के साथ शिकायत दर्ज करना शामिल है, प्रतिवादी संख्या 2 ने इस तरह के उपाय का सहारा नहीं लिया है और यह सोचा है कि यह आपराधिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त है, जो न्यायालय की राय में, कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है।

15. आपराधिक शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि उसी दिन, विद्वान मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित किया है।

शिकायत की सामग्री किसी भी आवेदक संख्या 2 से 5 की किसी भी विशिष्ट भूमिका को प्रकट नहीं करती है ताकि धारा 406 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके,

भारतीय दंड संहिता की धारा 408 और 420 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बयान में कहा है। यह सुझाव देने के लिए कोई आरोप नहीं है कि किसी भी आवेदक ने पहले गलत तरीके से प्रस्तुत किया था

शिकायतकर्ता ताकि लेनदेन में प्रवेश करने के उसके निर्णय को प्रभावित किया जा सके। वास्तव में, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि शिकायतकर्ता ने किसी भी शेयर लेनदेन के संबंध में आवेदकों से कभी मुलाकात की थी। वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है।"

14. उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, वह प्रस्तुत करता है कि उक्त मामला

भी इस तरह के विवाद के संबंध में बिक्री के तंत्र से उत्पन्न हो रहा है और इसे देखते हुए इस अदालत द्वारा प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था।

15. उपरोक्त आधारों पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

16. इसके विपरीत, श्री आरएस मजूमदार, ओपी संख्या 2 के लिए पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने *आपराधिक विविध याचिका संख्या* 669/2008 के पैरा -5, 21, 27, 28 और 29 पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि इसमें उल्लिखित तथ्य गलत हैं और भौतिक तथ्यों को छिपाकर, वर्तमान *आपराधिक विविध याचिका* दायर किया गया है। अनुलग्नक -ए में निहित अतिरिक्त जवाबी हलफनामा दाखिल करने के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेज का उल्लेख करते हुए, वह प्रस्तुत करता है कि मध्यस्थता मामला एआरबीए संख्या 166/2008 पहले ही 23.04.2008 को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा निपटाया जा चुका था, जिसमें वर्तमान आपराधिक विविध याचिका 13.05.2008 को दायर किया गया था और आपराधिक विविध याचिका संख्या 669/2008 के पैरा -5, 21, 27, 28 और 29 में कहा गया है कि उक्त मध्यस्थता कार्यवाही बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि इस आधार पर ही, आपराधिक विवध याचिका खारिज होने के योग्य है।

17. अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने ***अमर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भरोसा किया।(***2011) 7 एससीसी 69 **में रिपोर्ट किया गया** है, जहां पैरा -60 से 62 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है: -

> ***"60.*** *दलीप सिंह के अंतिम नोट किए गए मामले में [(2010) 2 एससीसी 114: (2010) 1 एससीसी (Civ) 324: JT (2009) 15 SC 201] , यह न्यायालय इस अवधारणा को एक नया आयाम दिया है जिसका दूरगामी प्रभाव है। इसलिये, हम उन सिद्धांतों को यहाँ फिर से दोहराते हैं: (SCC pp. 116-17, paras 1-2)*

1. कई शताब्दियों तक भारतीय समाज ने जीवन के दो बुनियादी मूल्यों को पोषित किया, अर्थात् 'सत्य' (सत्य) और 'अहिंसा'। महावीर, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी ने लोगों को अपने दैनिक जीवन में इन मूल्यों को शामिल करने के लिए मार्गदर्शन किया। सत्य न्याय-वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग था जो स्वतंत्रता-पूर्व युग में प्रचलित था और लोग परिणामों की परवाह किए बिना अदालतों में सच्चाई बताने में गर्व महसूस करते थे। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हमारी मूल्य प्रणाली में भारी बदलाव देखा गया है। भौतिकवाद ने पुराने लोकाचार को ढंक दिया है और व्यक्तिगत लाभ की तलाश इतनी तीव्र हो गई है कि मुकदमेबाजी में शामिल लोग अदालती कार्यवाही में झूठ, गलत बयानी और तथ्यों के दमन का सहारा लेने में संकोच नहीं करते हैं।

2. पिछले 40 वर्षों में, वाद कार्यों का एक नया पंथ पैदा हुआ है। जो लोग इस पंथ से संबंधित हैं, उनमें सत्य के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वे बेशर्मी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए झूठ और अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। वादियों के इस नए पंथ द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए, अदालतों ने समय-समय पर नए नियम विकसित किए हैं और अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक वादी, जो न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो दूषित हाथों से न्याय के शुद्ध फव्वारे को छूता है, किसी भी राहत का हकदार नहीं है, अंतरिम या अंतिम।

हालाँकि, यह न्यायालय यह देखने के लिए विवश है कि उन सिद्धांतों को उनके पालन की तुलना में उल्लंघन में अधिक सम्मानित किया जाता है।

***61.** इन सिद्धांतों का पालन करते हुए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि तत्काल रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा तुच्छ आरोपों के आधार पर और ऊपर बताए गए और चर्चा किए गए भौतिक तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने का एक प्रयास है। तथ्यों की ऐसी गलत प्रस्तुति के मद्देनजर, इस न्यायालय ने*

नोटिस जारी किया था और बाद में निषेधाज्ञा आदेश भी पारित किया था जो अभी भी जारी है।

62. *इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका को खारिज करता है और अंतरिम आदेश को रद्द करता है*

और याचिकाकर्ता के मामले के गुण-दोष, यदि कोई हो, को तय करने के लिए नहीं कहा जाता है। आपराधिक मामले के मद्देनजर वैधानिक अधिकारियों के खिलाफ टेलीफोन टैप करने का कोई मामला नहीं बनता है और विशेष रूप से याचिकाकर्ता के रुख को देखते हुए कि वह उस मामले में जांच से संतुष्ट है।

18. इसी तर्ज पर उन्होंने उमेश कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ***के मामले में भी भरोसा किया।,*** 2022 SCC में सभी 655 को ऑनलाइन **रिपोर्ट किया गया**। पैरा -15, 16 और 18 से 22 को नीचे उद्धृत किया गया है: -

15. *चूंकि, आवेदकों ने इस न्यायालय से साफ हाथों से संपर्क नहीं किया है और इस न्यायालय के समक्ष झूठा हलफनामा दायर किया है कि मामले से समझौता किया गया है, इसलिए, वह इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के पात्र नहीं हैं।*

16. कानून की अदालतें पक्षों के बीच न्याय प्रदान करने के लिए होती हैं। जो न्यायालय में आता है, उसे बेदाग हाथों से आना चाहिए और किसी भी तात्विक तथ्य को छिपाना नहीं चाहिए। मैं यह मानने के लिए विवश हूं कि अधिक बार अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग बेईमान वादियों द्वारा अपने नापाक डिजाइन को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस व्यक्ति का मामला झूठ पर आधारित है, उसे अदालत जाने का कोई अधिकार नहीं है। उसे मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर बाहर निकाला जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या दुरुपयोग का साधन नहीं बन सकती है या न्याय को नष्ट करने की प्रक्रिया में एक साधन नहीं बन सकती है, इस कारण से कि न्यायालय केवल न्याय को आगे बढ़ाने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

18. *न्यायालयों ने सदियों से वादियों पर नाक-भौं सिकोड़ी है, जिन्होंने अदालतों को धोखा देने और गुमराह करने के इरादे से तथ्यों के पूर्ण प्रकटीकरण के बिना कार्यवाही शुरू की।*

19. चंद्र शशि बनाम अनिल कुमार वर्मा, (1995) 1 एससीसी 21 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया:

> *अदालत ने कहा, "अदालतों को अपने कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप रोकने में सक्षम बनाने के लिए, जो लोग झूठी गवाही देने, छल-कपट और झूठ फैलाने जैसे अनैतिक कृत्यों में लिप्त हैं, उनके साथ उचित तरीके से निपटना होगा*
>
> *जिसके बिना, किसी भी अदालत के लिए सही अर्थों में न्याय का प्रशासन करना संभव नहीं होगा और उन लोगों की संतुष्टि के लिए जो इस उम्मीद में संपर्क करते हैं कि सत्य अंततः प्रबल होगा। लोगों को अदालतों पर भरोसा होगा जब वे पाएंगे कि (सत्य की ही जीत) वहां एक प्राप्त करने योग्य उद्देश्य है; या (यह पुण्य है जो जीत में समाप्त होता है) न केवल प्रतीक में अंकित है, बल्कि वास्तव में अदालतों के पोर्टल में होता है "*

*20. बुद्धि कोटा सुब्बाराय (डॉ.)*बनाम *के. परासरन, (1996) 5 एससीसी 530) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया:*

> *आवेदक द्वारा अपनाया गया पाठ्यक्रम अनुमेय है और उसका आवेदन कानून और तथ्यों की गलत धारणा पर आधारित है। किसी भी वादी को अपने मामलों को अपनी इच्छानुसार निपटाने के लिए अदालत के समय और सार्वजनिक धन पर असीमित सूखे का अधिकार नहीं है। न्याय तक आसान पहुंच का गलत या तुच्छ याचिकाएं दायर करने के लाइसेंस के रूप में दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बार में किए गए सबमिशन के साथ-साथ आवेदन के ज्ञापन में निहित लोगों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमारी राय है कि यह आवेदन गलत है, अस्थिर है और इसमें कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।*

21. अरुणिमा बरुआ बनाम भारत संघ (2007) 6 एससीसी 120 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह पुराना प्रचलित कानून है कि न्यायालय को अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने में

सक्षम बनाने के लिए दमन को भौतिक तथ्य होना चाहिए। भौतिक तथ्य का अर्थ लिस के निर्धारण के उद्देश्य से सामग्री होगा। यह आगे कहा गया कि अदालत के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाले व्यक्ति को गंदे हाथों से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम भारतीय स्टेट बैंक, (2007) 8 एससीसी 449 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया:

> *"यह अच्छी तरह से तय है कि एक विशेषाधिकार उपाय निश्चित रूप से कोई मामला नहीं है। असाधारण शक्ति का प्रयोग करने में, इसलिए, एक रिट कोर्ट वास्तव में उस पार्टी के आचरण को ध्यान में रखेगा जो इस तरह के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर रहा है। यदि आवेदक खुलासा नहीं करता है*
>
> *पूर्ण तथ्यों या प्रासंगिक सामग्री को दबाता है या अन्यथा न्यायालय को गुमराह करने का दोषी है, न्यायालय मामले को स्थगित किए बिना कार्रवाई को खारिज कर सकता है। यह नियम व्यापक जनहित में विकसित किया गया है ताकि बेईमान उत्तरदाताओं को न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से रोका जा सके। रिट क्षेत्राधिकार का आधार सत्य, पूर्ण और सही तथ्यों के प्रकटीकरण में निहित है। यदि भौतिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता है या दबा दिया जाता है या विकृत किया जाता है, तो रिट अदालतों का कामकाज असंभव हो जाएगा।*

22. केडी शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, (2008) 12 एससीसी 481 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी वादी अदालतों के साथ "लुका-छिपी नहीं खेल सकता है या "पिक एंड चूज" नहीं अपना सकता है। अदालत की रिट आयोजित करने के लिए स्पष्ट तथ्यों और साफ छाती के साथ आना चाहिए। भौतिक तथ्यों का दमन या छिपाना एक वादी के लिए या यहां तक कि वकालत की तकनीक के रूप में भी मना किया जाता है। ऐसे मामलों में न्यायालय नियम का निर्वहन करने के लिए बाध्य है और ऐसे आवेदक को अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अदालत की अवमानना के लिए निपटाया जाना आवश्यक है।

19. वह आगे आपराधिक विवध याचिका संख्या 669/2008 के पैरा -15 का उल्लेख

करता है और प्रस्तुत करता है कि 21.01.2008 को, ओपी संख्या 2 के खाते में 35,621.00 रुपये का डेबिट बैलेंस था और दोपहर के भोजन के बाद डेबिट बैलेंस ओपी संख्या 2 के खाते में 3,45,307.88 रुपये था, जिसके लिए याचिकाकर्ता-कंपनी ने पहले ही 27.01.2008 को ओपी संख्या 2 को नोटिस जारी कर दिया है। जिसमें मध्यस्थता मामला सं. एआरबीए संख्या 166/2008 बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दायर किया गया था ताकि कानूनी लागत के रूप में 25,000 रुपये के साथ 3,45,307.88 रुपये वसूल किए जा सकें। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 14.02.2008 को, यह कहा गया है कि उन्होंने मार्जिन/प्रतिभूतियों के शेयर बेचे थे और 1,90,611/- रुपये की राशि का विनियोजन किया था और आगे 18.02.2008 [जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-एफ] पर, 3,45,307.88 रुपये का मांग पत्र जारी किया गया था। वह प्रस्तुत करता है कि यदि 1,90,611/- रुपये की राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है, तो याचिकाकर्ता कंपनी के लिए 3,45,307.88 रुपये की मांग करने का कोई अवसर नहीं था, इस तरह, 1,90,611/-

याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा दुवनियोजन और उस मांग के लिए, याचिकाकर्ता कंपनी पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष मध्यस्थता मामला दायर कर चुकी है।

20. इसके मद्देनजर वह प्रस्तुत करता है कि सौंपना वहां है और याचिकाकर्ता कंपनी के साथ-साथ अन्य लोगों द्वारा भी उल्लंघन किया गया है। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने ***2022 SCC ऑनलाइन SC 1061/2022*** में रिपोर्ट किए **गए** एमएनजे भारतीश रेड्डी **बनाम रमेश रंगनाथन** के मामले में भरोसा किया, जहां पैरा -20 से 23 में इसे इस प्रकार आयोजित किया गया है: -

> *20.* भरतीय दण्ड संहिता की धारा *405* आपराधिक विश्वास भंग के बारे में बतती है *का* और निम्न तरह पढ़ी जाती है:
>
> ***"405.*** आपराधिक विश्वास भंग - *जो कोई, किसी रीति से संपत्ति को सौंपा जा रहा है, या संपत्ति पर किसी प्रभुत्व के साथ, बेईमानी से दुवनियोजन करता है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित करता है, या उस संपत्ति का*

बेईमानी से उपयोग या व्ययन विधि के किसी भी दिशा में करता है जिसमें उस तरीके को निर्धारित किया गया है जिसमें इस तरह के ट्रस्ट का निर्वहन किया जाना है, या किसी कानूनी संविदा का, व्यक्त या निहित है, जिसे उसने ऐसे भरोसे के निर्वहन को छूने के लिए बनाया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित किया है,

" आपराधिक विश्वास भंग करता है"

21. आपराधिक विश्वास भंग का *अपराध* के *दो तत्व होते हैं: (i) किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के साथ, या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपना; और (ii) जिस व्यक्ति को सौंपा गया है, वह बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग के लिए परिवर्तित होता है, जिसने इसे सौंपा है* उसके विरूद्ध अपने हित में प्रयोग करता है

22. अनवर चंद सब नानादिकर बनाम *कर्नाटक राज्य दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में आपराधिक विश्वासघात के अपराध के आवश्यक अवयवों को दोहराया:*

> ***"7.** धारा 405 के तहत आरोपों को घर लाने की बुनियादी आवश्यकता संयुक्त रूप से साबित करने की आवश्यकताएं हैं (1) सौंपना, और (2) क्या अभियुक्त को बेईमान इरादे से सक्रिय किया गया था या इसका दुरुपयोग नहीं किया गया था या इसे अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित किया गया था जो इसे सौंपे गए व्यक्तियों की हानि के लिए था। जैसा कि इरादे का सवाल प्रत्यक्ष प्रमाण का मामला नहीं है, कुछ व्यापक है*
>
> *परीक्षणों की परिकल्पना की गई है जो आम तौर पर यह तय करने में उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि क्या किसी विशेष मामले में अभियुक्त ने अपराध के लिए दुराशय रखा था*

23. विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य[7] *में, एक अन्य दो-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि संपत्ति का आवंटन आईपीसी की धारा 405 के तहत अपराध*

का गठन करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पढ़ता है:

> ***"28.** दंड संहिता, 1860 की धारा 405 के तहत संपत्ति का "सुपुर्द" इसके तहत अपराध का गठन करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रयुक्त शब्द हैं, किसी भी तरीके से संपत्ति को सौंपा गया। इसलिए, यह सभी प्रकार के सौंपे जाने तक फैला हुआ है, चाहे क्लर्क, नौकर, व्यापार भागीदार या अन्य व्यक्तियों को, बशर्ते वे "विश्वास" की स्थिति धारण कर रहे हों। एक व्यक्ति जो लगाए गए दायित्व की शर्तों के विपरीत उन्हें सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है, वह आपराधिक विश्वास भंग के लिए उत्तरदायी है और दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडित किया जाता है।*

21. उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, वह प्रस्तुत करता है कि विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के संबंध में दो सामग्री बनाई गई है,

यानी सौंपना और बेईमानी से दुरुपयोग।

22. मध्यस्थता के संबंध में, वह प्रस्तुत करता है कि यदि मध्यस्थता खंड होने पर भी आपराधिकता की जाती है, तो आपराधिक मामले को बनाए रखा जा सकता है और उसने ***प्रीति सराफ बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) के मामले में भरोसा किया, (***2021) 16 एससीसी 142 **में रिपोर्ट किया गया**, जहां पैरा -31 से 34 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

> ***"31.** वर्तमान मामले में, शिकायत/एफआईआर/आरोप पत्र को ध्यान से पढ़ने पर, हमारे विचार से, यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायत अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है। शिकायत/एफआईआर/ आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों के आधार पर धारा 406 और 420 आईपीसी के तहत अपराधों की सामग्री को अनुपस्थित नहीं कहा जा सकता है। हम यह जोड़ना चाहेंगे कि शिकायत में लगाए गए आरोप अन्यथा सही हैं या नहीं, इसका निर्णय मुकदमे के दौरान किए जाने वाले सबूतों के आधार पर किया जाना है। सिर्फ इसलिए कि*

अपीलकर्ताओं के कहने पर शुरू की गई अनुबंध या मध्यस्थ कार्यवाही के उल्लंघन के लिए एक उपाय प्रदान किया गया है, जो स्वयं अदालत को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाता है कि सिविल उपचार ही एकमात्र उपाय है, और आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत, किसी भी तरीके से, ऐसी कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

32. *हमने पक्षों की दलीलों, शिकायत/एफआईआर/* आरोप पत्र *और निचली अदालतों के आदेशों का अवलोकन किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को ध्यान में रखा है। पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि विचाराधीन मामले में शामिल मुद्दा ऐसा मामला नहीं है जिसमें आपराधिक मुकदमे को शॉर्ट-सर्किट किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा अपने निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना न्यायोचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से दो परिस्थितियों पर विज्ञापन दिया है,*

(१) कि यह अनुबंध के कथित उल्लंघन के कारण बेचने के लिए समझौते की समाप्ति का मामला था और;

(२) तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं के कहने पर मध्यस्थ कार्यवाही शुरू की गई है।

उच्च न्यायालय द्वारा देखी गई दोनों कथित परिस्थितियां, हमारे विचार में, कानून में अस्थिर हैं। वर्तमान शिकायत/एफआईआर/आरोप-पत्र में वर्णित तथ्य वास्तव में वाणिज्यिक लेनदेन को प्रकट करते हैं, लेकिन यह शायद ही यह मानने का कोई कारण है कि धोखाधड़ी का अपराध इस तरह के लेनदेन से बच जाएगा। वास्तव में, कई बार, वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी का अपराध किया जाता है और धारा 415, 418 और 420 आईपीसी के तहत उदाहरण निर्धारित किए गए हैं।

33. *इसी तरह की टिप्पणियां इस न्यायालय द्वारा ट्रिसन केमिकल इंडस्ट्री बनाम* राजेश अग्रवाल

मामले में की गई हैं। [ट्रिसन केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल, (1999) 8 एससीसी 686: 2000 एससीसी (सीआरआई) 47]: एससीसी पी. 690, पैरा 9

"9. हम इस तर्क की सराहना करने में असमर्थ हैं कि विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए समझौते में शामिल प्रावधान आपराधिक अभियोजन के लिए एक प्रभावी विकल्प है जब विवादित कार्य एक अपराध है। मध्यस्थता समझौते के उल्लंघन से प्रभावित पार्टी को राहत देने के लिए एक उपाय है, लेकिन मध्यस्थ किसी भी कार्य का परीक्षण नहीं कर सकता है जो अपराध की राशि है, हालांकि एक ही अधिनियम समझौते के तहत किसी भी कार्य के निर्वहन से जुड़ा हो सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए दहलीज पर ही शिकायत को रद्द करने के लिए ये अच्छे कारण नहीं हैं। जांच एजेंसी को आरोपों के सभी पहलुओं में जाने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। इस तरह की जांच का पूर्व-निष्कासन केवल बहुत ही चरम मामलों में उचित होगा जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्प (1) एससीसी 335: 1992 एससीसी (सीआरआई) 426] में दर्शाया गया है।

34. जहां तक मध्यस्थता *कार्यवाही शुरू करने का संबंध है, इसका आपराधिक कार्यवाहियों से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ दायर आरोप-पत्र पर भी गौर नहीं किया है, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर था कि किसी भी आपराधिक अपराध को प्रथम दृष्टया बनाया जा रहा है और इसकी सत्यता की वास्तव में आपराधिक मुकदमे के दौरान जांच की जानी चाहिए।*

23. जहां तक आपराधिक विवध याचिका संख्या 1241/2016 के तथ्यों का संबंध है, उन्होंने इस आधार पर रद्द करने का विरोध किया कि 28.01.2008 को, याचिकाकर्ता कंपनी ने

ओ.पी. संख्या 2 और दिनांक 14.02.2008 के पत्र द्वारा, मार्जिन/सिक्योरिटी शेयर

1,90,611/- रुपये की बिक्री की गई थी और 01.07.2009 को, एकमात्र मध्यस्थ ने एक अवार्ड पारित किया और ओपी संख्या 2 को अवार्ड की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर 1,56,017.64 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसके खिलाफ ओपी संख्या 2 ने मुकदमा दायर किया है, याचिकाकर्ता कंपनी ने यह कहते हुए जवाब दायर किया है कि ओपी संख्या 2 1,56,017.64 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, हालांकि, उक्त राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है।

याचिकाकर्ता कंपनी, जिसे दिनांक 08.10.2009 के पत्र द्वारा प्रमाणित किया गया है, जो 2008 के आपराधिक विवध याचिका संख्या 669 में ओपी संख्या 2 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-जी में निहित है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद 3,45,307.88 रुपये की और मांग की गई। वह आगे प्रस्तुत करता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 36 के आलोक में, यदि पुरस्कार लागू नहीं किया जाता है, तो जिस व्यक्ति के पक्ष में पुरस्कार है, वह सक्षम सिविल कोर्ट के समक्ष जा सकता है, हालांकि, याचिकाकर्ता कंपनी ने उक्त खंड को लागू नहीं किया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि ओपी संख्या 2 ने दुमका में विद्वान अदालत के समक्ष एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें उक्त राशि के भुगतान के लिए प्रार्थना की गई है। इन आधारों पर, ओपी संख्या 2 के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि आपराधिकता बनाई गई है और यदि आपराधिकता बनाई जाती है, तो नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों को बनाए रखा जा सकता है।

24. संबंधित मामलों में राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक लोक अभियोजक संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप हैं और यदि आपराधिकता की बात कही जाती है, तो सिविल और आपराधिक दोनों मामलों को बनाए रखा जा सकता है।

25. ओपी संख्या 2 के लिए पेश होने वाले विद्वान वकील के तर्क के जवाब में, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री ओंकार नाथ तिवारी ने प्रस्तुत किया कि मामला एक समझौते से उत्पन्न हो रहा है और वह अदालत

को उक्त समझौते के कई खंडों में ले गए, जो आपराधिक विविध याचिका संख्या 1241/2016 के अनुलग्नक -3 में निहित है और खंड 1.6 का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करता है कि सदस्य के चरणों को नियंत्रित किया जाएगा सेबी के नियमों और विनियमों द्वारा। क्लॉज-1.7.2.1 का हवाला देते हुए वह प्रस्तुत करता है कि ओपी संख्या 2 ने पूरे समझौते को पढ़ा है। क्लॉज-1.7.2.2 का हवाला देकर वह प्रस्तुत करता है कि ओपी संख्या 2 जिम्मेदार है। क्लॉज-1.7.2.4 को संदर्भित करने के माध्यम से वह प्रस्तुत करता है कि उक्त खंड ग्राहक की बात करता है कि ग्राहक प्रारंभिक मार्जिन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, मार्जिन को रोक रहा है, विशेष मार्जिन या ऐसे अन्य मार्जिन। क्लॉज-1.7.5 का हवाला देते हुए वह आगे कहता है कि कंपनी परिसमापन या बंद आउट करने के लिए अधिकृत है। वह आगे खंड 1.7.13 का उल्लेख करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि मध्यस्थता खंड है। वह आगे समझौते के खंड-1.7.23 और 1.7.25 का उल्लेख करता है और प्रस्तुत करता है कि ये

याचिकाकर्ताओं के समर्थन में है और मामला एक नागरिक प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है, इस मामले के मद्देनजर, पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

26. पक्षकारों की ओर से पेश विद्वान वकीलों की उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, अदालत ने सभी मामलों में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का अध्ययन किया है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता कंपनी और याचिकाकर्ता शेयरों के साथ कारोबार कर रहे हैं और सेबी के साथ पंजीकृत भी हैं। ओपी संख्या 2 ने वर्ष 2006 में निवेश के ग्राहक के रूप में हाथ मिलाया और उसके बाद उसका खाता नियमित रूप से उक्त कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था, क्योंकि उस कोड के लिए डीमैट खाता ओपी संख्या 2 को प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ ओपी संख्या 2 के लिए पेश होने वाले विद्वान वकील के तर्क में उद्धृत दूसरी राशि को कंपनी द्वारा विवाद उत्पन्न होने के लिए परिसमाप्त कर दिया गया था।

27. आपराधिक विविध याचिका संख्या 669/2008 के पैरा -5, 21, 27, 28 और

29 में, यह खुलासा किया गया है कि मध्यस्थता केस संख्या एआरबीए संख्या 166/2008 बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, जिसमें वर्तमान मामला 13.05.2008 को इस अदालत के समक्ष दायर किया गया है। ओपी संख्या 2 द्वारा दायर अतिरिक्त जवाबी हलफनामे में अनुलग्नक-ए में निहित दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताता है कि उक्त मध्यस्थता मामले का निपटारा 23.04.2008 को ही कर दिया गया था, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस तथ्य को दबाते हुए, वर्तमान मामला दायर किया गया है।

28. आपराधिक विविध याचिका संख्या 669/2008 के पैरा -15 में, यह कहा गया है कि ओपी संख्या 2 के खाते में 35,621.00 रुपये डेबिट बैलेंस था, जबकि 22.01.2008 को, यह कहा गया था कि ओपी संख्या 2 के खाते में लंच के बाद डेबिट बैलेंस 3,45,307.88 रुपये दिखाया गया है, इसके लिए याचिकाकर्ता-कंपनी ने पहले ही 27.01.2008 को ओपी संख्या 2 को नोटिस जारी किया है और उस राशि के लिए खुद को मध्यस्थता मामला सं. एआरबीए संख्या 166/2008 बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष उक्त राशि की वसूली के लिए दायर किया गया था। 28.01.2008 को अनुलग्नक- डी में निहित, ओपी संख्या 2 ने ओपी संख्या 2 के खाते में किसी भी आगे के लेनदेन को रोकने के लिए एक पत्र जारी किया। 14.02.2008 के अनुलग्नक -ई में रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेज बताता है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा 1,90,611/- रुपये का मार्जिन/सिक्योरिटी शेयर पहले ही बेच दिया गया था। तथापि, अनुलग्नक -एफ में निहित दिनांक 18-02-2008 के पत्र द्वारा मांग की गई थी

रु. 3,45,307.88 इसके मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा 1,90,611/- रुपये की राशि का गबन किया गया था और याचिकाकर्ता उक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक हैं।

29. इसके अलावा पीसीआर केस संख्या 192/2010 (टीआर संख्या 387/2016), जो 2016 के आपराधिक विविध याचिका संख्या 1241 की विषय वस्तु है, ओपी संख्या 2 ने पहले ही दुमका में विद्वान सक्षम अदालत के समक्ष एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा जवाब दायर किया गया

था, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुलग्नक-एच में निहित जवाब दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता 1,56,017.64 रुपये वसूलने का हकदार है। जबकि अनुलग्नक-जी द्वारा, ओपी संख्या 2 का हिस्सा पहले ही 1,56,017.64 रुपये की बिक्री की जा चुकी है, इस तरह, इसे पहले से ही एकमात्र मध्यस्थता पुरस्कार के संदर्भ में वसूल किया गया था और उक्त मुकदमे में जवाब में, याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा यह कहा गया था कि कंपनी द्वारा 1,56,017.64 रुपये वसूल किए जाने योग्य हैं।

30. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कंपनी के गुणवत्ता के समान मानक तक नहीं था और स्पष्ट रूप से सौंपने और धोखाधड़ी का मामला बनता है, हालांकि, यह केवल मुकदमे में विद्वान अदालत द्वारा तय किया जा सकता है, जहां मामला अभी भी लंबित है।

31. संज्ञान/कार्यवाही, वाणिज्यिक लेनदेन का निरस्तीकरण और मध्यस्थ कार्यवाही अनुकरण का तथ्य नहीं है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता के कहने पर शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही के लिए अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपाय प्रदान किया गया है, जो स्वयं अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य नहीं करता है कि सिविल उपचार केवल उपाय है और आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत ऐसी कार्यवाही को रद्द करने के लिए निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में प्रीति सराफ और अन्य के मामले में स्पष्ट रूप से विचार किया गया ***है। (सुप्रा)।*** इसमें कोई संदेह नहीं है कि समझौते में एक मध्यस्थता खंड है कि याचिकाकर्ता कंपनी और याचिकाकर्ताओं ने चीजों को कैसे दबा दिया है और यहां तक कि 1,90611 रुपये की राशि भी काट ली है, जैसा कि निपटाया गया है (सुप्रा)। इस प्रकार यदि तथ्य का ऐसा विवादित प्रश्न है, तो उच्च न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है कि यह नागरिक प्रकृति का मामला है।

32. जहां तक आपराधिक विविध याचिका संख्या 1241/2016 और 669/2008 को याचिकाकर्ताओं के तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री सिंह के द्वारा ***विजय कुमार घई (सुप्रा)***, ***एस.के. गोयल एवं अन्य। (सुप्रा) के*** मामलों पर भरोसा

किया गया है जिसमें न्यायालय इस बात से सहमत है कि यदि कार्यवाही की सिविल प्रकृति है, तो उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इसके बजाय उच्च न्यायालय के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है कि यदि कोई मामला दुर्भावनापूर्ण रूप से दायर किया जाता है, तो वह चीजों के गुण अर्थ को निकाल लें, हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यह धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने का मामला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री सिंह द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील याचिकाकर्ताओं की मदद नहीं कर रहे हैं।

33. जिस तरह से आपराधिक विविध याचिकाओं के दायर करने में कुछ छिपाया जाता है, उसने इस अदालत को यह देखते हुए रोक दिया कि सच्चाई न्यायिक वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जिसे स्वतंत्रता-पूर्व युग में लागू किया गया था और लोग परिणाम की परवाह किए बिना अदालतों में उक्त सच्चाई लाते रहते थे और इस पहलू पर अमर सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से निपटा गया है उमेश ***कुमार यादव (सुप्रा) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ-साथ।***

34. आपराधिक विश्वास भंग के अपराध में दो तत्व होते हैं जो किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति में या संपत्ति के किसी भी डोमेन के साथ सौंपते हैं और जिस व्यक्ति को सौंपा गया है वह बेईमानी से दुरुपयोग करता है या इसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए कवर करता है, उस संपत्ति को उस व्यक्ति के समायोजन के लिए जिसे सौंपा गया है।

35. वर्तमान मामले के तथ्यों में राशि के समायोजन के बावजूद, उक्त का दावा मध्यस्थता कार्यवाही में किया गया था और मध्यस्थता कार्यवाही के निस्तारण के बावजूद, याचिका में कहा गया है कि उक्त मध्यस्थता कार्यवाही लंबित है। इसके अलावा विद्वान अदालत के समक्ष ओपी संख्या 2 द्वारा दायर मुकदमे के जवाब में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर जवाब में, यह कहा गया है कि 1,56,017.64 रुपये की वसूली की आवश्यकता है, जिसमें उक्त राशि पहले ही शेयरों को बेचकर वसूल की जा चुकी है, जो 2016 के सीआरएमपी

संख्या 1241 में ओपी संख्या 2 द्वारा दायर काउंटर एफिडेविट के अनुलग्नक-जी में निहित है।

36. उपरोक्त तथ्यों, कारणों और विश्लेषण के मद्देनजर, अदालत ने पाया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने का मामला नहीं है।

37. तदनुसार, इन सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है। लंबित आईए, यदि कोई हो, खारिज कर दिया जाता है।

38. यह स्पष्ट किया जाता है कि बिचारण न्यायालय इस आदेश से पूर्वाग्रह के बिना कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ेगा, क्योंकि यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के सिद्धान्तो पर विचार करते हुए पारित किया गया है

अमितेश/-

[ए.एफ.आर.]

(संजय कुमार द्विवेदी, जे.)

[यह अनुवाद शिववचन यादव , पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया]

(४)